



**VISIONIAS**  
INSPIRING INNOVATION  
**ABHYAAS MAINS**

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-IV)/GENERAL STUDIES (Paper-IV) (4513)**

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: 250  
Maximum Marks: 250

**सामान्य अनुदेश**

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 62+2 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

**General Instructions**

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 62+2 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 00 623655

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Apurva Verma

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी  
Medium: Hindi/English

English

तारीख  
Date

27.07.25

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-IV)  
GENERAL STUDIES (Paper IV)**

केंद्र  
Centre Lilawati Widya Mandir

Riyash  
निरीक्षक के हस्ताक्षर  
Invigilator's Signature

	<p style="text-align: center;"><b>महत्वपूर्ण अनुदेश</b></p> <p>उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।</p>	<p style="text-align: center;"><b>Important Instructions</b></p> <p>Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.</p>
1	<p>(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें।</p> <p>(ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।</p>	<p>(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates.</p> <p>(b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet</p>
2	<p>अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।</p>	<p>Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.</p>
3	<p>परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।</p>	<p>Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.</p>
4	<p>उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।</p>	<p>Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.</p>
5	<p>उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि अरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।</p>	<p>Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.</p>
6	<p>प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।</p>	<p>Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.</p>
7	<p>प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।</p>	<p>Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.</p>
8	<p>यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।</p>	<p>If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.</p>

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

**प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))**

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1(a)			6 (a)		
1(b)			6 (b)		
2(a)			7		
2(b)			8		
3(a)			9		
3(b)			10		
3(c)			11		
4(a)			12		
4(b)					
5(a)					
5(b)					
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
<b>सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)</b>					



**VISIONIAS**  
INSPIRING INNOVATION  
**ABHYAAS MAINS**

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-IV)/GENERAL STUDIES (Paper-IV) (4513)**

निर्धारित समय: तीन घंटे  
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: **250**  
Maximum Marks: **250**

**प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश**

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बारह प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

**QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS**

*Please read each of the following instructions carefully before attempting questions:*

There are **TWELVE** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both, in **HINDI** and in **ENGLISH**.

*All questions are compulsory.*

*The number of marks carried by a question/part is indicated against it.*

*Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.*

*Keep the word limit indicated in the questions in mind.*

*Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.*

## EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. (a) करुणा, दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानकर उसे महसूस करने तथा उस संबंध में कार्रवाई करने का साहसी विकल्प है, तब भी जब मौन रहना अधिक सुरक्षित हो और उदासीनता दिखाना अधिक सहज हो। भारत में सिविल सेवकों के लिए एक आवश्यक नैतिक मूल्य के रूप में करुणा के महत्त्व का परीक्षण कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Compassion is the courageous choice to feel another's suffering as one's own, and to act upon it, even when silence is safer and indifference is easier. Examine the significance of compassion as an essential ethical value for civil servants in India. Illustrate your answer with suitable examples. (Answer in 150 words)

10

Compassion has been defined as one of the 4 cardinal values by Plato. It encompasses the feeling of understanding other's pain as well as taking measures to help.

▷ Significance of compassion as an essential ethical value:

① Working for the most marginalised sections of the society.

↳ Eg: Transgender Act, 2019 empowers transgender community.

② Increasing association of people with

government's programs and initiatives.  
Eg: Mao's like Narmada Bachao Andolan  
highlighting government initiatives's  
shortcomings.

③ Breaking social capital in the society:

↳ Eg: Kiran Bedi's Prison Reforms  
created a new life to many inmates.

④ Increasing virtues and trust in  
governance process

↳ Eg: Government's PM- Garib Kalyan  
Anna Yojana during COVID-19.

⑤ Innovative and out of box thinking  
to help people.

↳ Eg: Special trains for migrant workers  
during COVID-19.

Compassion may be called as building  
block of a society based on human  
trust and ethics.

1. (b)

भारत में विवाह पारंपरिक संस्कारों से हटकर अधिक स्वायत्त संबंधों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती प्रवृत्ति और बढ़ती तलाक दरों से परिलक्षित होता है। इन परिवर्तनों के नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

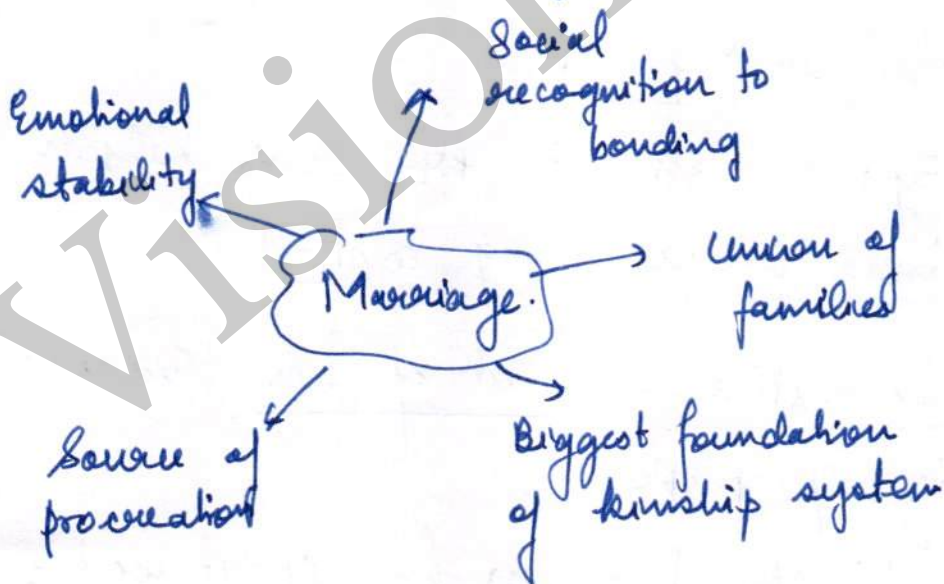
Marriages in India are transitioning from traditional sacramental unions to more autonomous relationships, reflected in live-in relationships and rising divorce rates. Discuss the ethical dimensions of these changes. (Answer in 150 words)

10

Marriage has been defined as an essential element of India's societal structure.

According to NCRB data, the divorce rate has increased by 50% since 2010.

▷ Ethical dimensions of the changes:



① Feeling of possessive individualism over communitarian elements:

↳ Partners are adamant on their way of life.

② Breakdown of families and impact on mental stress:

↳ According to NCRB data, 60% of women were found to have committed suicide due to interpersonal relations

③ Impact on children and other family members:

↳ Feeling of insecurity and emotional crisis.

④ Rising cases of infidelity -

↳ Erosion of social capital.

⑤ Lack of community oversight leading to commission of crime.

↳ Shradha Walkar Murder case.

Marriages are truly regarded as anthropogenic specimen of societal development and organization. There is a need to adapt to upcoming challenges.

2. (a)

यद्यपि जवाबदेही के लिए प्रायः प्रलेखन आवश्यक होता है, लेकिन नौकरशाही प्रक्रियाओं और अत्यधिक कागजी कार्रवाई पर अधिक बल देने से अनजाने में उन आवाजों को दबाया जा सकता है जिन्हें लोक नीति, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, सशक्त करना चाहती है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ उपर्युक्त कथन का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

While accountability often necessitates documentation, an overemphasis on bureaucratic procedures and excessive paperwork can inadvertently silence the very voices that public policy intends to empower, particularly at the grassroots. Examine the above statement with suitable illustrations. (Answer in 150 words)

10

Accountability has been regarded as one of the foundational values of civil services. It refers to the holding oneself available to justify the decisions taken.

▷ Excessive accountability and its impact:

① Can create defiance towards legitimate policy goals and decisions

↳ Eg: CAG's reports suggest impeachable suggestions sometimes.

② Causes bureaucratic apathy and red tapism

↳ More focus on paperwork and less

on actual outcome.

③ Lack of any change in the ground level realities.

↳ Eg: Focus is on paperwork only.

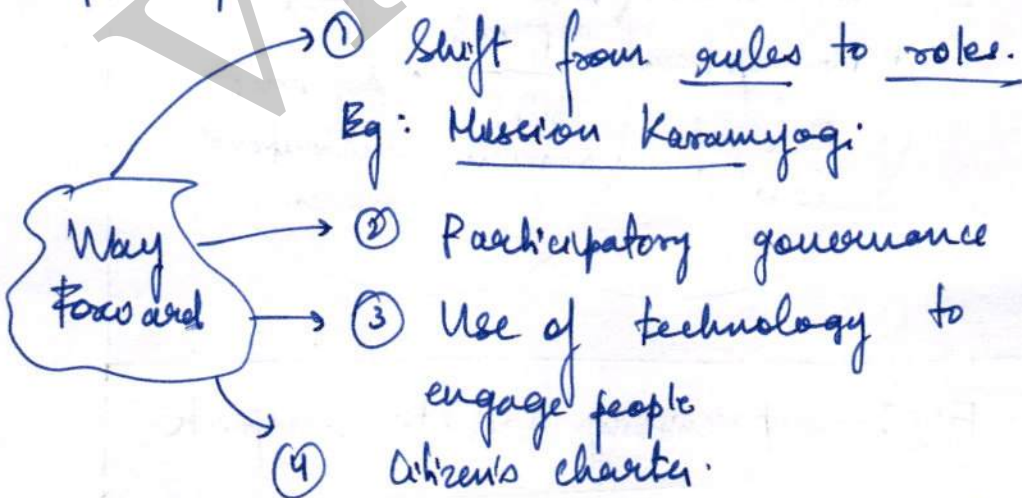
↳ Vyapam scam.

④ One-size fit all approach discourages genuine public needs.

↳ Eg: Failure of Mahalanobis model in agricultural field.

⑤ Erosion of public trust in governance.

↳ Eg: RTI Act has empowered people's participation.



Accountability has to be balanced with transparency and objectivity for true success.

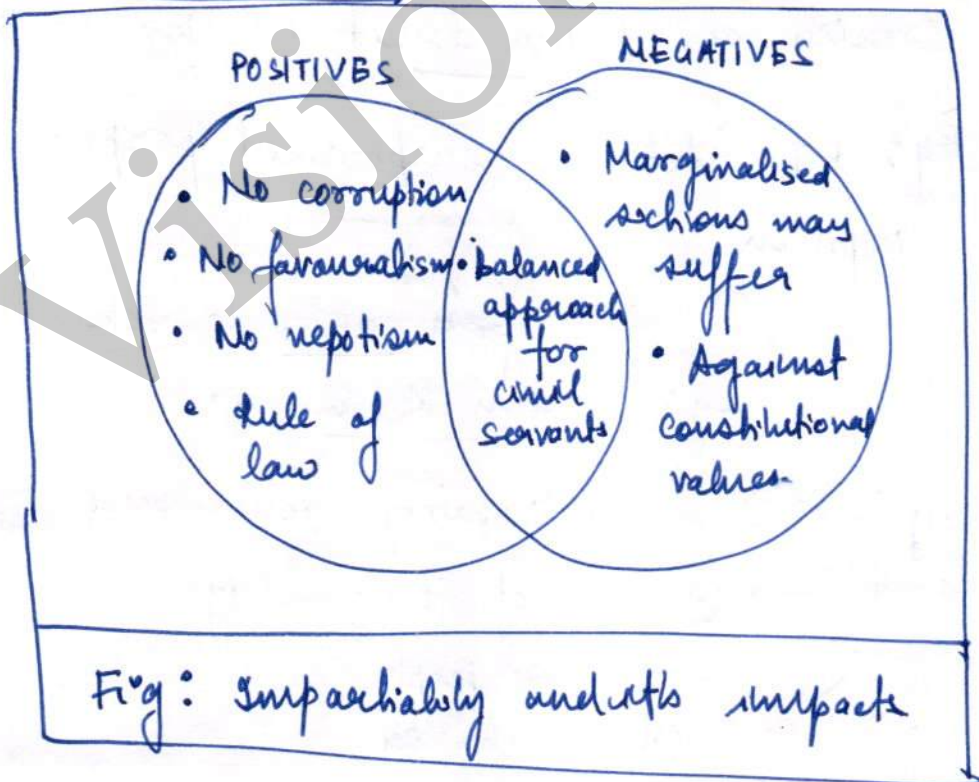
2. (b) निष्पक्षता के सिद्धांत का कभी-कभी वंचित समुदायों के प्रति करुणा की आवश्यकता के साथ टकराव हो सकता है। भारत में सिविल सेवाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The principle of impartiality may conflict with the need for compassion towards marginalized communities. Discuss in the context of civil services in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हिसाब में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

Impartiality is the first virtue in any civil service. It refers to treating everyone alike without any discrimination.  
However, even our constitution encompasses positive discrimination.

▷ Impartiality in context of civil services in India:



① India has a large population under poverty. Impartiality may not be completely useful in gaining socio-economic development.

↳ Eg: Starvation deaths in Theerkhund due to strict adherence to rules.

② Affirmative justice is compromised:

↳ Article - 14 : Equals should be treated alike. However, for affirmative policies, positive discrimination has to be done.

③ Impartiality may not suffice in case of marginalised sections unaware of their rights.

④ Impartiality gives importance to instinctive ones population for whom they have been created.

Impartiality is essential but it is not mandatory when it comes to ensuring socio-economic justice.

3. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What do each of the following quotations mean to you?

(a) "किसी राष्ट्र की ताकत उसके घर की अखंडता से उत्पन्न होती है।" - कन्फ्यूशियस (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"The strength of a nation derives from the integrity of the home." - Confucius (Answer in 150 words)

10

"State is individual writ large", according to Plato. It means state comprises of its people and take the same shape as the quality of its people.

Home forms the basic social unit of any nation: A nation may be defined as comprising a number of homes. So, the teachings which are given at home will ultimately define the character of the nation.

Examples:

① Patriotism curricula being promoted in schools. When the child goes back at home and learns the

same, his values and mortality inculcate patriotism as an essential value.

② Increasing rate of divorces and family disputes is evident in the form of broken homes and rising juvenile crimes -

↳ Eg: As per NCRB, there has been 200% increase in the rate of juvenile crimes in Delhi.

③ Home is the first school for any child. It is the source of values, moral compass, conditioning of child who later on become adults.

④ Homes when resilient and based on moral grounds cultivate some best minds

↳ Eg: Gandhiji's philosophy derived from mother.

Homes and nations are both integral parts of individuals and impart their character.

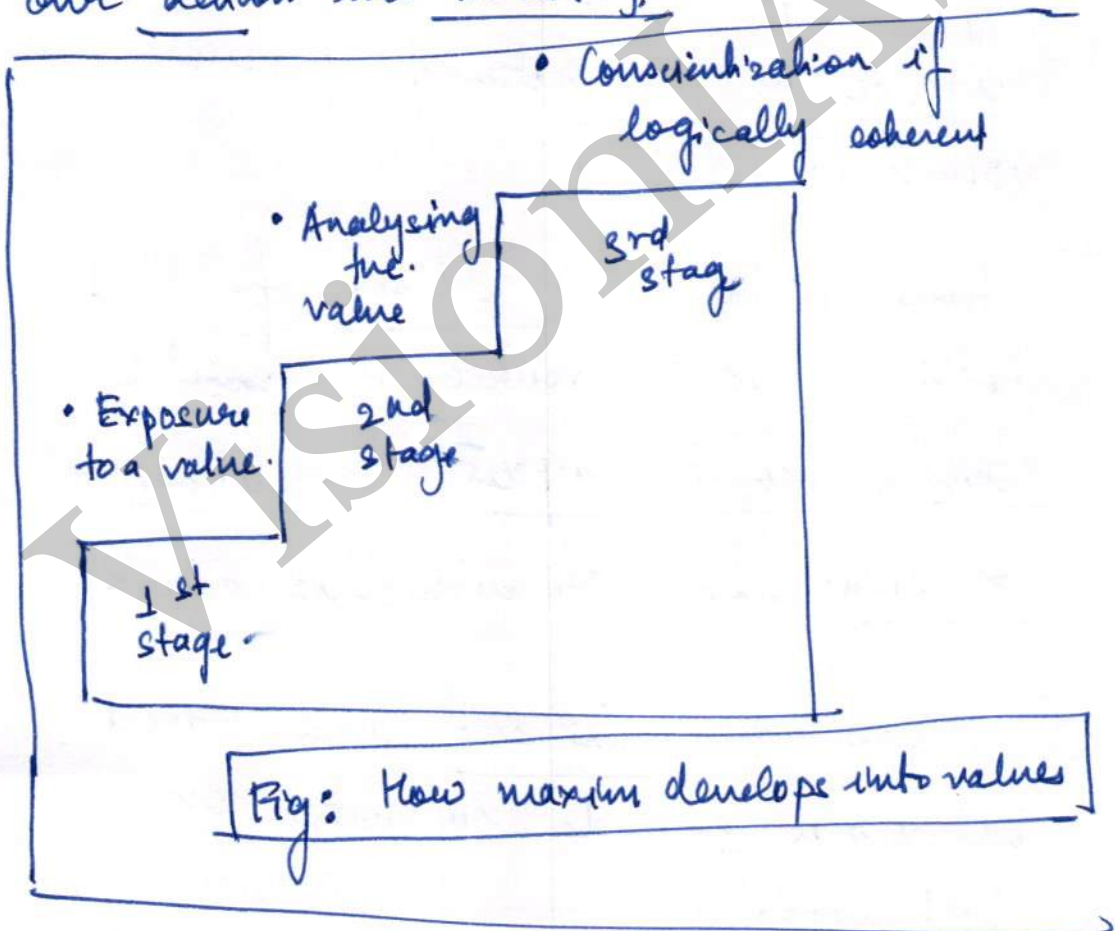
3. (b) "उसी नियम के अनुसार आचरण करें जिसके बारे में तत्क्षण आप सार्वभौमिक विधि बनाने का संकल्प कर सकें।"- इमानुएल काण्ट (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
- "Act only according to that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law."- Immanuel Kant (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस हफ्ते में नही लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

10

In life, we come across different value systems and ethical dilemmas.

We can experience cognitive dissonance if there is lack of coherence between our action and thinking.



▷ According to Kant, deontological

ethics, there has to be morally acceptable justification for actions.

▷ An action cannot be against moral principles whatever be the reason.

▷ It has to have justification in all philosophies and should be based on some universal values.

Example:

① Killing an enemy soldier may not be morally justified though it is part of just war theory.

② Ends and means cannot be separated.

③ Continuous filtering of thoughts and actions to remove redundancies

The ideas of Kant in above quote establish grounds for a harmonious society.

3. (c)

“हम न केवल उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो हम करते हैं, बल्कि उसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं जो हम करने में विफल रहते हैं।” - मोलियर (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“We are not only responsible for what we do, but also for what we fail to do” - Molière. (Answer in 150 words)

10

उम्मीदवारों को इस क्राशिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

As said by Mahatma Gandhi, human beings cannot separate ends and means. All our actions and thought process have to be based on morally sound principles.

The above quote highlights responsibility we have towards all our actions - committed or not-committed. We are responsible not only for actions we have done and gone wrong but also actions we did not take to stop the injust.

Examples:

① During Uttarakhand floods, 2013, the

administration was slow in the rescue leading to loss of lives.

↳ However, due to their apathy towards disaster-preparedness, they were also held accountable.

② 3 children died of starvation in Jharkhand due to lack of action raised:

▷ Administration was to be questioned why they were not responsive to ration card.  
A At the same time, why no action was taken to prevent the death.

③ Social evils prevalent in society:

▷ If we see a case of eve-teasing, it is not just important to take action but also teach our family and friends of doing the same.

Our actions may be a matter of life and death and we should always be mindful of that.

4. (a)

देशभक्ति नैतिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि राष्ट्रवाद प्रायः इसका दमन करता है। अत्यधिक दबाव वाली राष्ट्रीय घटनाओं के दौरान राजनीतिक अभिवृत्तियों के विकास के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। व्यक्ति ऐसी नैतिक अभिवृत्तियों को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय हित और नैतिक तर्क के बीच संतुलन स्थापित करें? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Patriotism encourages ethical questioning, while nationalism often suppresses it. Discuss this statement in light of the formation of political attitudes during high-pressure national events. How can individuals develop moral attitudes that balance national interest with ethical reasoning? (Answer in 150 words)

10

Patriotism refers to the value of commitment of feelings, values towards one's nation irrespective of different identity markers. Nationalism on the other hand propounds one homogenous identity.

▷ Formation of political attitudes:

① Exposure to political ideas:

② Development of aversion or inclination based on our pre-existing values.

③ Reinforcing of idea through process of social conditioning.

▷ Eg: Peer pressure.  
Social groups

- ④ Sensationalisation of attitudes  
through yellow journalism
- ⑤ Conformity bias due to social media

▶ Developing moral attitude that balance  
national interest with ethical reasoning.

- ① Inter-party dialogues based on  
logical debate:
- ② Media as educator through ethical  
reporting.
- ③ Shedding rigidity and open to  
different ideas
- ④ Cultivating a culture of debate  
and discussion.
- ⑤ Credible facts and figures to  
understand situation.

As per Buddha's "Madhyama Marg", there  
is a need to balance in order to  
maximise our thought process.

4. (b)

चर्चा कीजिए कि निजी संगठनों में कर्मचारी कल्याण और निष्पक्षता को दक्षता एवं लाभप्रदता के साथ किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss how employee well-being and fairness can be balanced with efficiency and profitability in private organisations. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हार्शिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

In private organisations, there is a need to balance individual well-being with organisational well-being. As promoted by Narayan Murthy, there is a need for ethical capitalism.

▷ Balancing employees well-being and fairness with organisations efficiency and profitability:

① Support for mental health and genuine physiological needs.

↳ Eg: Paternity leave, Menstrual leave

② Focus on cultivating an atmosphere of transparency and accountability

③ Building social capital and  
involving in inter-personal relationships  
↳ Eg: Team visits and excursions.

④ Ensuring gender equality and gender  
sensitivity:

↳ Eg: Pink toilets for females having  
basic amenities

↳ Sanitary pad vending machines.

⑤ Zero tolerance for discrimination:

↳ Eg: Strict implementation of POSH  
Act.

⑥ Regular breaks to re-energise mind  
and time-bound debency.

Employee well-being forms the central  
theme of any organisation's successful  
functioning.

5. (a)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सोशल मीडिया और उभरती हुई ए.आई. प्रौद्योगिकियों के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में भावनात्मक नियमन और नैतिक संवेदनशीलता में कमी आ सकती है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree that excessive use of social media and emerging AI technologies may lead to a decline in emotional regulation and moral sensitivity among adolescents? Justify your answer. (Answer in 150 words)

10

Social media and AI technologies have been defined as "new age weapons". Their speed of spread and control with massive reach makes them dual use tools.

▷ In support of social media and AI:

- ① Helps in generating social capital.
  - ② Builds social networking and helps in solving community problems.
  - ③ Useful for coaching of government and NGOs.
- ▷ Eg: Messages during disasters.

① Helps in educating the masses.

▷ Against the use of social media and AI:

① Use of deep fakes and misinformation creates erosion of social trust.

② Circulation of videos with inappropriate content impacts adolescents.

▷ Eg: Boy's lockerroom incident of Delhi.

③ Use of social media by terrorist organisations

▷ Eg: Use of ISIS through telegram.

④ Number of cyber crimes through social media:

▷ Cyber stalking; Bullying; Malware, etc

Social media and AI need to be regulated because of the immense potential which is beyond comprehension power of human mind.

5. (b)

भारत में छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के आलोक में, चर्चा कीजिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ई.आई.) तनाव और भावनात्मक चुनौतियों के प्रबंधन में किस प्रकार सहायता कर सकती है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In light of the increasing incidents of suicides among students in India, discuss how Emotional Intelligence (EI) can aid in managing stress and emotional challenges. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हार्शिए में नहीं लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

Emotional Intelligence refers to understanding one's emotions as well as other's emotions resulting in heightened sensitivity and better interpersonal skills.

▷ EI as aid to students:

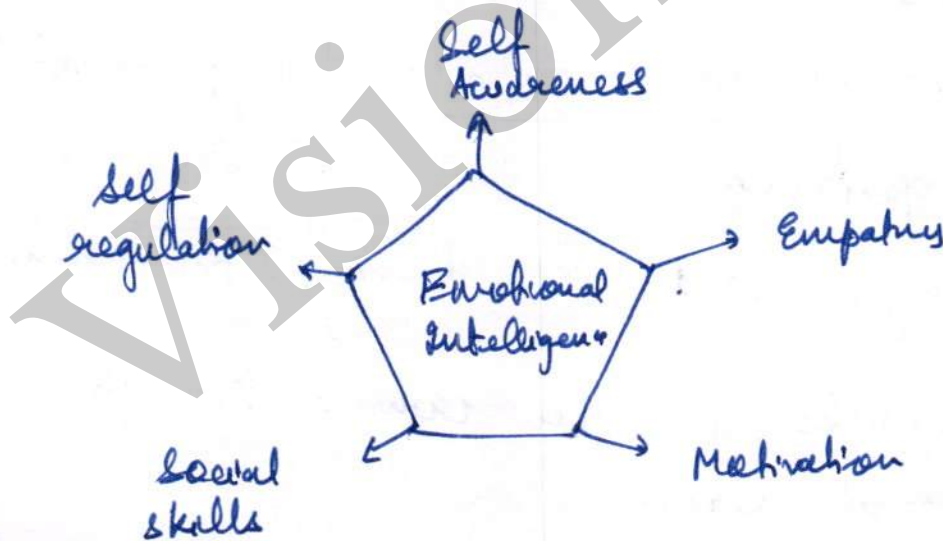


Fig: Emotional Intelligence component

① End the hesitation of students to

take help from stress.

- ② Help in better managing one's emotions and dissuade negative thoughts.
- ③ Better communication and expression with parents helps in solving any complications.
- ④ Better handling of stress and setbacks.
- ⑤ EI acts as guide to rebound and move further towards goal.
- ⑥ EI helps in solving ethical dilemmas.
- ⑦ Removes cognitive dissonance.

EI is rightly called to contribute around 80% in our success. Be it inherent or learned, it is a quint-essential.

6. (a)

लोक सेवा में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समानुभूति और शक्ति के साथ दूसरों से जुड़ने, तनाव या टकराव शांत करने तथा उनका उत्थान करने के इसके उद्देश्य में निपुणता प्राप्त करना है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In public service, emotional intelligence is not about suppressing emotion, but mastering its purpose — to connect, to de-escalate, and to uplift others with empathy and strength. Do you agree with this view? Discuss. (Answer in 150 words) 10

Emotional intelligence has been regarded as important for a civil servant to tackle everyday challenges. According to 2nd ARC, EI forms the bedrock for civil servants.

▷ Use of emotional intelligence in public service:

A) To connect:

① EI helps in building interpersonal relations with different sections

② Creates mutual trust between citizens and administration.

③ Policies are more responsive resulting

in° further connection of people.

B) To de-escalate.

① EI helps in tackling challenging situations.

↳ Eg: Tackling clash in a communally sensitive area.

② Deal with conflicts and prevent escalation with others

③ Maintain a healthy atmosphere in organisation.

C) To uplift others:

① Keeping in° mind sensitivities of different sections.

↳ Eg: K. Sundarajan while leading Kudumbashree in Kerala

② Out of box solutions:

↳ T. N. Sheshan for enforcement of MCC.

EI offers vast opportunities for organisations strengthening and moral boosting.

6. (b)

एक कुशल कार्य संस्कृति का निर्माण केवल नियमों पर नहीं, बल्कि साझा मूल्यों पर आधारित होता है। इस संदर्भ में, किसी संगठन के भीतर कार्य संस्कृति को परिवर्तित करने में नेतृत्व और टीम के पारस्परिक व्यवहार के तरीके की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

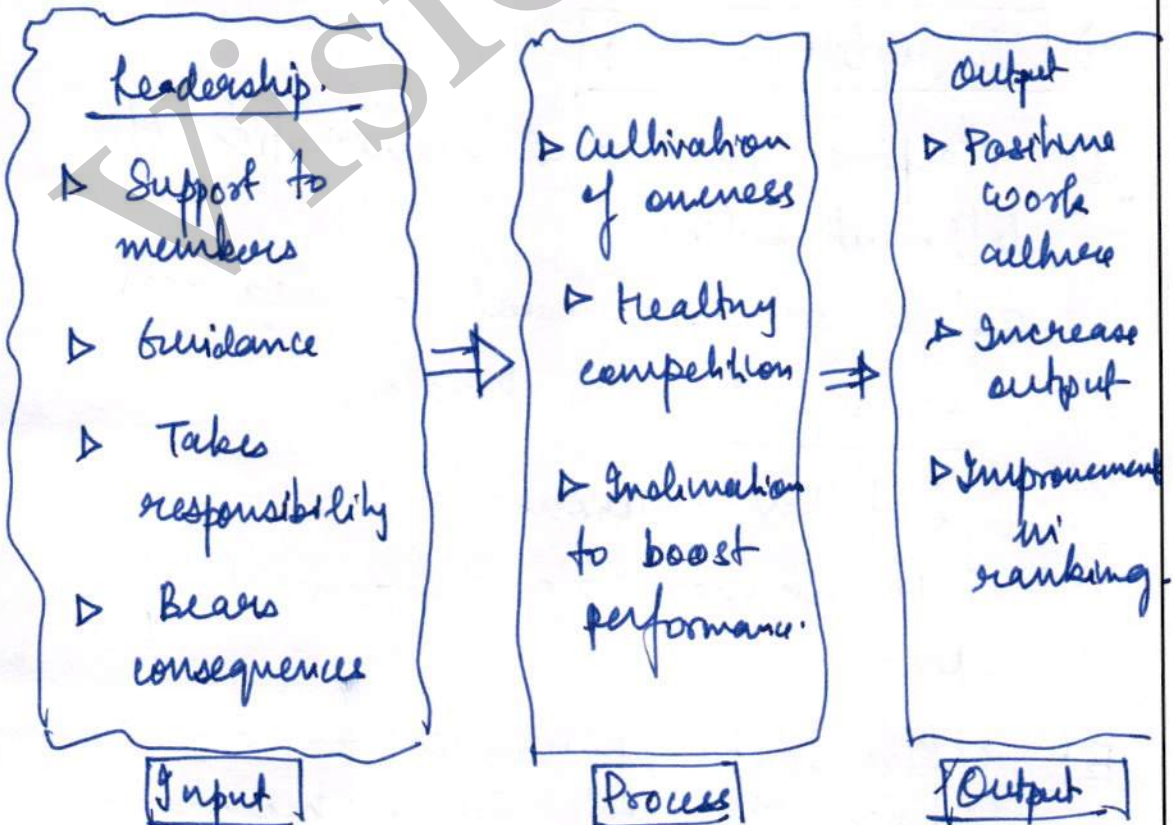
An efficient work culture is built not only on rules, but on shared values. In this context, evaluate the role of leadership and team dynamics in transforming work culture within an organization. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस हार्फ में नही लिखना चाहिए  
Candidates must not write on this margin

10

Members of a team swim and sink together. This line forms the basic philosophy of team dynamics.  
Leaders form the keystone of this team setup.

▷ Role of leadership and team dynamics in transforming work culture:



① Leadership sets the tone for other members

↳ Eg: Nikam Sarabhai took responsibility for failure.

② Cultivates a sense of belongingness:

↳ Helps in transforming individuals to a team.

③ Understands the strengths of each member.

↳ Helps in streamlining the task.

④ Cultivates values advantageous for the organisation.

↳ Punctuality, responsive.

⑤ Tackles corruption, red-tapism and apathy:

↳ Being quick in times of need.

Leadership helps in joining discreet elements as one single entity helping in achieve goals.

7.

आप एक राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में, सरकार ने कई नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं लागू की हैं, जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में निवासियों से व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जा रहा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के अनुसार, ऐसे डेटा को केवल स्पष्ट और सूचित सहमति के साथ ही संसाधित किया जाना चाहिए और यदि व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले लेता है, तो डेटा का संसाधन तुरंत रोकना अनिवार्य है।

एक आंतरिक ऑडिट के दौरान, आपको पता चलता है कि विभाग कई नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को उनके द्वारा अपनी सहमति औपचारिक रूप से वापस लेने के बावजूद संसाधित और विश्लेषित कर रहा है। इस डेटा का उपयोग नीति विश्लेषण और सेवा सुधार जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जो डेटा एकत्र करते समय स्पष्ट रूप से बताए नहीं गए थे। जब आप इस मुद्दे को विभाग प्रमुख के संज्ञान में लाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि डेटा संसाधन को रोकने से चल रही डिजिटल पहलें बाधित हो सकती हैं और राज्य स्तर के प्रदर्शन संकेतक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको यह भी पता चलता है कि सहमति वापसी की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है और अधिकांश नागरिकों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है।

आपको यह भी पता चलता है कि एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत डेटा के बिना सहमति के उपयोग के विरुद्ध डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है, जिससे विभाग के विरुद्ध सार्वजनिक जांच और विधिक कार्रवाई हो सकती है।

- (a) इस प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करते हुए उन पर चर्चा कीजिए।
- (b) यदि इस मुद्दे का पारदर्शी तरीके से समाधान नहीं किया गया तो विभाग के लिए संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?
- (c) आप कुशल लोक सेवा वितरण की आवश्यकता और नागरिकों के डेटा अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are posted as the Joint Secretary in the Department of Information Technology of a state. The government recently implemented several citizen-centric digital services, collecting large volumes of personal data from residents. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, requires that such data be processed only with explicit and informed consent, and mandates that processing must cease immediately upon withdrawal of consent.

During an internal audit, you discover that the department continues to process and analyze personal data of several citizens even after they have formally withdrawn their consent. This data is being used for policy analytics and service improvement, purposes not explicitly disclosed at the time of data collection. When you bring this to the attention of your department head, you are informed that halting the processing will disrupt ongoing digital initiatives and may affect state-level performance metrics. Moreover, you find that the consent withdrawal process is cumbersome, and many citizens are unaware of their rights under the DPDP Act.

You also learn that a prominent social activist is planning to file a complaint with the Data Protection Board against involuntary use of personal data, which could attract public scrutiny and legal action against the department.

- (a) Identify and discuss the ethical issues involved in this case.
- (b) What are the potential consequences for the department if the issue is not addressed transparently?
- (c) How would you balance the need for efficient public service delivery with the obligation to protect citizens' data rights? (Answer in 250 words)

20

The present case is a classic example of clash between individual well-being and organisational functioning.

In this case, right to privacy is being compromised which has been declared as a fundamental right under Article-21 in Puttaswamy judgement.

Stakeholders involved:

- ① Common public whose data has been collected.
- ② Government department - (IT)
- ③ Media
- ④ Joint secretary of department.
- ⑤ Social activist
- ⑥ Future generations
- ⑦ SC as it's judgement not being upheld.

(a) Ethical issues involved:

- ① Right to privacy vs organisational efficiency.
- ② Contempt of court.
- ③ Organisational apathy towards evolving policy.
- ④ Rigid bureaucratic structures.
- ⑤ Secrecy and lack of transparency.
- ⑥ Legislative fraud on common people.
- ⑦ Erosion of social trust.
- ⑧ Misuse of data analytics.

(b) Potential consequences for the department:

- ① Sensationalisation of the news:
  - ↳ Eg: Similar incidents during Pegasus spyware.
  - ↳ Cambridge Analytica case.

② Chance of judicial action:

↳ Against provisions of the DPDP Act.

③ Public outrage when news comes out:

↳ Mistrust between government and people.

④ Law and order situation:

↳ Chances of strikes and public protest.

⑤ Departmental enquiry on all involved.

▷ Balancing between need for efficient public service delivery and citizens data rights:

① Create a statutory body under the act to maintain oversight of any violations of the act.

- ② Streaming the process of giving and withdrawal of consent.
- ③ Engage civil societies to maintain constant vigil.
- ④ Seek public cooperation for implementation of policies related to digital India mission.
- ⑤ In case of any violation, immediately halt the misuse of data.
- ⑥ Maintaining transparency regarding processing of data.
- ⑦ Every department to have ethics charter and governance redressal mechanism.

Maintaining check on data misuse as important in the long run towards a digitalised society.

8.

आप एक IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में एक पहाड़ी राज्य में लोक निर्माण विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में, एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो अभियंताओं से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। एक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना के निरीक्षण के दौरान, मंत्री को कथित रूप से एक वीडियो में सार्वजनिक रूप से अभियंताओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया। यह वीडियो वहां से गुजर रहे लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तथा टेलीविजन चैनलों द्वारा भी इसे व्यापक रूप से कवर किया गया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश और समर्थन दोनों देखने को मिला। बाद में मंत्री ने अपने कृत्य का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी भ्रष्ट हैं, स्थानीय शिकायतों के प्रति अनुत्तरदायी हैं और परियोजना में अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि उसका व्यवहार जनता की निराशा और दूरस्थ क्षेत्र में समय पर अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता से प्रेरित था।

हालांकि, अभियंताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर यह दावा किया है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने मंत्री से जुड़े स्थानीय ठेकेदारों को ठेका देने के लिए डाले जा रहे राजनीतिक दबाव का विरोध किया था। स्थिति के अधिक गंभीर होने पर, NHAI अभियंताओं के एक संघ ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई और अधिकारी की गरिमा की रक्षा की मांग करते हुए हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके कारण कई महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं ठप हो गई हैं, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क, मानसून पूर्व मरम्मत कार्य और सामरिक सीमा सड़कें शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने आपको तथ्यान्वेषण रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच, मंत्री का कार्यालय आप पर अनौपचारिक रूप से घटना को कम महत्वपूर्ण दिखाने का दबाव बना रहा है। मीडिया दो भागों में बंटा हुआ है — कुछ मंत्री को भ्रष्टाचार के विरुद्ध योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे प्रशासनिक आचरण और विधि के शासन का गंभीर उल्लंघन बता रहे हैं। विभिन्न विभागों के सिविल सेवकों ने व्यक्तिगत सुरक्षा, गरिमा और राजनीतिक हस्तक्षेप की बढ़ती घटनाओं के संबंध में चिंता व्यक्त की है, वहीं अवरुद्ध अवसंरचना कार्यों के कारण नागरिकों में भी असंतोष बढ़ रहा है।

- इस प्रकरण में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं? हितधारकों और उनके परस्पर विरोधी हितों की पहचान कीजिए।
- लोक निर्माण विभाग के सचिव के रूप में, आप उपर्युक्त स्थिति में क्या कार्रवाई करेंगे?
- ऐसी घटनाएं सिविल सेवकों के मनोबल और शासन में जनता के विश्वास को कैसे प्रभावित करती हैं? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are an IAS officer, currently serving as the Secretary of the Public Works Department in a hill state. Recently, a disturbing incident has come to light involving a senior Cabinet Minister and two engineers of the National Highways Authority of India (NHAI). During an inspection of a critical highway project, the Minister was allegedly seen on video physically assaulting and verbally abusing the engineers in full public view. The video, recorded by bystanders, went viral on social media and was widely covered by television channels, sparking both outrage and support from different sections of society. The Minister later defended his actions, alleging that the officials were corrupt, unresponsive to local grievances, and responsible for inordinate delays in the project. He insisted that his actions were driven by public frustration and the urgency of delivering infrastructure to a remote region.

However, the engineers have filed a police complaint and written to their superiors, claiming they were targeted for resisting political pressure to award contracts to specific local contractors linked to the Minister. As the situation escalated, a union of NHAI engineers declared a strike,

demanding action against the Minister and protection of officer dignity. This has brought several critical infrastructure projects to a standstill, including road connectivity to tribal areas, pre-monsoon repair works, and strategic border roads.

You have been directed by the Chief Secretary to prepare a fact-finding report, while also ensuring smooth coordination between state and central agencies. Meanwhile, the Minister's office is informally pressuring you to downplay the incident. The media is sharply divided — some portraying the Minister as a crusader against corruption, others condemning the act as a serious breach of administrative ethics and rule of law. Civil servants across departments have expressed concern about personal safety, dignity, and increasing political interference, while citizens are now growing restless due to halted infrastructure works.

- (a) What are the key ethical issues involved in this situation? Identify the stakeholders and their conflicting interests.
- (b) As the Secretary of the PWD, what actions will you take in above situation?
- (c) How do such incidents affect the morale of civil servants and public trust in governance?  
(Answer in 250 words)

20

Public services work on the basic foundation of justice. There is no scope for violence in the functioning of any department or by any public official. The above case highlights the complex interplay of this functioning.

▷ Stakeholders involved:

- ① Central government
- ② State government
- ③ Secretary, PWD
- ④ PWD Department

5) NHAI engineers.

6) Minister

7) Political parties

8) Media

9) Judiciary

10) Police officials

11) Common public

▷ Conflicting interests:

1) Between minister and NHAI engineers:

▷ Minister - downplaying incident, allegations of political pressure.

▷ NHAI engineers - Allegations of corruption, apathy in work.

2) Secretary, PUP and minister:

▷ Minister wants to downplay incident

▷ Secretary has to give an honest fact-finding report.

3) Police vs political parties:

▷ ~~Less~~ Political party pressurizing

police from taking action.  
▷ Police under political pressure.

(b) Actions in the above situation:

- ① Legal action against minister for physical assault on government servants.
- ② Analysing and investigating both angle of corruption from minister and engineers's perspective.
- ③ Asking the NHA engineers to end strike after legal action and expedite the work.
- ④ Asking police to stop spread of fake news and viral video's circulation on media.
- ⑤ Create a holistic report by

coordinating with different stakeholders and agencies.

(c) Impact on morale of public servants and trust in governance:

① Lack of enthusiasm to work in public servants.

↳ Eg: attacks on doctors during COVID-19.

② Erosion of public trust in governance.

③ Mis-reporting of incidents leads to political violence further aggravating suffering of common people.

④ Lack of people's participation in government programs

⑤ Public protests

↳ Eg: Anna Hazare for Jan Lokpal Bill.

Any form of violence must be dealt with serious actions to deter any future incident.

9.

आप भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल के वर्षों में, लोक सेवकों, विशेष रूप से IAS, IPS और IRS से संबंधित ऐसे युवा अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज बना रहे। इन प्लेटफार्मों पर, वे नियमित रूप से अपने आधिकारिक कार्यों — नवाचारी परियोजनाओं, जनसंपर्क पहलों, निरीक्षण यात्राओं और कभी-कभी दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों - से संबंधित वीडियो भी पोस्ट करते हैं।

इन वीडियो पर प्रायः व्यापक रूप से जनता द्वारा ध्यान केंद्रित दिया जाता है और कई दर्शक यह कहते हुए इसकी सराहना करते हैं कि ऐसी सामग्री पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, अभ्यर्थियों को प्रेरित करती है और नौकरशाही को मानवीय बनाती है। हालांकि, विभिन्न वर्गों से कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। वरिष्ठ अधिकारी तर्क देते हैं कि ऐसी सामग्री व्यक्तिगत ब्रांडिंग और लोक सेवा के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकती है, जबकि कुछ नागरिक और मीडिया विश्लेषक ऐसे उदाहरणों की ओर संकेत करते हैं, जहां वीडियो में बिना सहमति के सुभेद्य लाभार्थियों को दिखाया जाता है, आधिकारिक परिसरों का दुरुपयोग किया जाता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो सार्वजनिक उत्तरदायित्व की तुलना में व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने हेतु बनाए गए हैं।

एक प्रकरण में, एक जिलाधिकारी को एक विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को कैमरे पर डांटते हुए देखा गया — यह वीडियो बाद में उनके व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया, जो मोनेटाइज भी है। कुछ लोगों ने अधिकारी द्वारा अपनाए गए सख्त रवैये की सराहना की, जबकि अन्य ने शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से डांटने और सेवा की गरिमा का उल्लंघन करने की आलोचना की। एक अन्य मामले में, एक पुलिस अधिकारी को बाढ़ बचाव अभियान का निर्देशन करते हुए देखा गया, जहां उसके कर्मचारी ड्रोन कैमरे में माध्यम से इसे फिल्मा रहे थे, जिसे बाद में सोशल मीडिया के लिए एक प्रेरणादायक वीडियो के रूप में संपादित किया गया। आपको लोकहित, संस्थागत सत्यनिष्ठा और संचार के बदलते तरीकों के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु अनुशंसाओं सहित एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

- लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के कृत्यों में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
- क्या ऐसी प्रथाएं जागरूकता और प्रेरणा को प्रोत्साहन देती हैं या क्या ये अनामिता, तटस्थता और सामूहिक सेवा भावना के मूल्यों से समझौता करती हैं? अपना मत दीजिए।
- सचिव के रूप में, लोक सेवकों की उत्तरदायी डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आप कौन-से मार्गदर्शक सिद्धांत और नीतिगत अनुशंसाएं सुझाएंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are the Secretary in the Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India. In recent years, an increasing number of civil servants, particularly younger officers from the IAS, IPS, and IRS, have begun maintaining personal YouTube channels and social media pages. On these platforms, they regularly post videos related to their official work — showcasing innovative projects, public outreach initiatives, inspection drives, and sometimes even day-to-day administrative duties.

These videos often receive widespread public attention, and many viewers express admiration, saying such content enhances transparency, motivates aspirants, and humanizes the bureaucracy. However, concerns have also emerged from various quarters. Senior officers argue that such content may blur the boundaries between personal branding and public service, while some citizens and media commentators point to instances where videos feature vulnerable beneficiaries without consent, raise concerns about misuse of official premises, or seem designed more for personal popularity than public accountability.

In one case, a district magistrate was seen filming a surprise school inspection in which teachers were scolded on camera — the video was later posted to his personal YouTube channel that is also monetized. While some praised the officer's strictness, others criticized the public shaming of teachers and the breach of service dignity. In another case, a police officer was seen directing a flood rescue operation while his staff filmed drone footage, later edited into a motivational video for social media. You have been asked to prepare a report with recommendations to balance public interest, institutional integrity, and evolving modes of communication.

- Identify the ethical issues involved in civil servants publicly showcasing their official work on social media.
- Do such practices promote awareness and motivation, or do they compromise the values of anonymity, neutrality, and collective service ethos? Give your opinion.
- As the Secretary, what guiding principles and policy recommendations would you suggest to ensure responsible digital engagement by civil servants? (Answer in 250 words) 20

Above case study points towards the growing nature of social media and as a spillover effect, it's intrusion in public service delivery. This may have both educative purpose as well as may be misused for personal gains.

(a) Ethical issues involved:

① Against the clause of secrecy in sensitive official works

→ Eg: Official Secrets Act, 1923.

② Monetisation of personal channels  
highlight the vested interest

↳ Against all India Conduct Rules sport

③ Against principle of anonymity of  
civil servants:

↳ Widespread presence on social media  
may dilute effective surprise  
element.

④ Violation of citizens privacy:

↳ Posting of content on social media  
without explicit content against  
spirit of DPDP Act.

⑤ Sensationalisation of generated content

↳ Eg: In above example, the teacher  
could have been handled in  
isolation rather than making

## Social media headlines.

### (b) Awareness or compromise:

Creates awareness and motivation.

Compromises values of anonymity

- ① Increases trust between people and government.
- ② Helps reaching out to underserved population.
- ③ Easy method of connecting to people.
- ④ Educate values as people watch functioning of government.
- ⑤ Shift from cloak of secrecy to participatory governance.

- ① Some sensitive details may be leaked unintentionally.
- ② Echo-chambers pressure others to do same.
- ③ Self interest and popularity is aim rather than genuine public good.

## ▷ Guiding principles and policy recommendations:

- ① Create a SOP for any posting of content on social media.
- ② Do not use personal accounts to showcase professional works  
↳ A separate professional account to portray engaging content.
- ③ Banning monetisation of social media accounts without departmental knowledge.
- ④ Cyber security for all user-generated content.
- ⑤ Including social media usage under All India Conduct Rules
- ⑥ Training under Mission Karmayogi.  
Social media engineering is important to maintain public contact but with strings attached.

10.

आप नेशनल बायोएथिक्स कमीशन के निदेशक हैं, जो एक राष्ट्रव्यापी जीन अनुक्रमण कार्यक्रम की नैतिक व्यवहार्यता और निगरानी का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। "जीन फ्यूचर" नामक इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक नवजात शिशु के डी.एन.ए का अनुक्रमण करना और उसे एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस में संग्रहित करना है। इसका उद्देश्य जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही गंभीर बीमारियों के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्तियों की पहचान करना है, ताकि निवारक उपचार और वैयक्तिकृत चिकित्सा संभव हो सके। इस कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण में पहले ही 1,00,000 से ज्यादा शिशुओं को नामांकित किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि यह जन स्वास्थ्य उन्नति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

यद्यपि, नवजात शिशुओं के आनुवंशिक डेटा का संग्रह गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है, विशेष रूप से सूचित सहमति के संबंध में, जो संभवतः दीर्घकालिक जोखिमों के बारे में माता-पिता की समझ को पूरी तरह से नहीं दर्शाती है। एक बार एकत्रित हो जाने के बाद, इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग निगरानी, बीमा भेदभाव या तृतीय पक्षों द्वारा व्यावसायिक विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डेटा के स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता—कि यह राज्य का है, माता-पिता का है, या उस बच्चे का है जब वह बयस्क होगा—इस मुद्दे को और जटिल बना देती है। निजी तकनीकी और दवा कंपनियों की संलिप्तता से वाणिज्यिक शोषण की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, विशेष रूप से इस प्रकार के स्पष्ट तंत्र के अभाव में, जिसके तहत बयस्क होने पर व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले सकता है या अपनी आनुवंशिक जानकारी को हटा सकता है।

- आपके विचार में जीन फ्यूचर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
- इस प्रकरण में विभिन्न हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों की पहचान कीजिए।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आप किन मार्गदर्शक नैतिक सिद्धांतों की अनुशंसा करेंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are the Director of the National Bioethics Commission who is responsible for assessing the ethical feasibility and oversight of a nationwide gene sequencing program. The project named GeneFuture, aims to sequence the DNA of every newborn child and store it in a centralized national database. The objective is to identify genetic predispositions to serious diseases early in life, allowing for preventive treatment and personalized medicine. Over 100,000 babies have already been enrolled in the pilot phase of the program. The government claims that this move is a landmark step in public health advancement.

However, collection of newborn genetic data raises significant ethical concerns, particularly around informed consent, which may not fully capture parents' understanding of the long-term risks involved. Once gathered, this sensitive data could be misused for purposes such as surveillance, insurance discrimination, or commercial marketing by third parties. Uncertainty over data ownership—whether it lies with the state, parents, or the individual as they mature—further complicates the issue. The involvement of private tech and pharmaceutical companies heightens fears of commercial exploitation, especially in the absence of clear mechanisms for individuals to withdraw consent or delete their genetic information upon reaching adulthood.

- What are the ethical issues you perceive in the implementation of the GeneFuture program?
- Identify the conflicting interests of different stakeholders in this case.
- What guiding ethical principles would you recommend for implementation of this project? (Answer in 250 words)

20

The above case-study points towards rising developments in the field of science and technology and associated privacy issues for the citizens. There is a need to deal with the matter in a comprehensive manner in the backdrop of increasing pace of development.

▶ Stakeholders involved:

- ① Newborn babies and their parents
- ② Government
- ③ Pharmaceutical and private tech companies
- ④ Director, National Bioethics committee
- ⑤ Media

(a) Ethical issues perceived;

- ① Right to privacy of newborn infants.
- ② Misuse by pharmaceutical and private tech companies
- ③ Ambiguity in withdrawal of consent.
- ④ Unawareness of parents of newborns.
- ⑤ Futuristic technologies may use data not consented for.

(b) Conflicting interests between stakeholders:

Government	People
▷ Research on data of infants	▷ Right to privacy being compromised.

▷ No transparency in usage of data.

▷ No grievance redressal mechanism

▷ Not provided with clear terms and conditions

▷ May be difficult in case of misuse

Pvt. companies

▷ May diversify use of data without consent

▷ May commercialise the data.

People.

▷ No provision for withdrawal of consent when infants turn adult.

(c.) Guiding ethical principles:-

① Citizen-centric policy to be framed for such utilisation of genetic data.

▷ Eg: EU's GDPR Act -

② Heavy fines and strict action  
against officials found violating  
terms and conditions

↳ Eg: Inclusion under BNS.

③ License cancellation for private  
companies not adhering to  
consent.

④ Right to be forgotten to be implicit  
in all such programs.

⑤ Time and storage of data.  
↳ Mandatory deletion after certain  
time.

⑥ Randomisation and anonymisation  
of data

With evolutionary technologies, there is  
a need to protect children's interests  
to safeguard both scientific development  
and personal well-being.

आप एक समर्पित जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) हैं और आप साक्ष्य-आधारित जन स्वास्थ्य पद्धतियों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखते हैं। हाल ही में, आपको भारत के एक दूरस्थ जिले में नियुक्त किया गया है। आपका तात्कालिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य एक प्रमुख जिला-व्यापी खसरा-रूबेला (MR) टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करना है, जिसका उद्देश्य 9 महीने से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में 100% टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है। इस अभियान की सफलता हजारों बच्चों के सामूहिक स्वास्थ्य और जिले के समग्र स्वास्थ्य संकेतकों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब आने वाला मानसून का मौसम स्वास्थ्य संबंधी अतिरिक्त चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।

हालांकि, आपके जिले के सबसे बड़े और सबसे पारंपरिक गाँवों में से एक में, आपको अत्यधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। एक प्रतिष्ठित स्थानीय आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि टीकाकरण दुष्ट आत्माओं का आक्रमण है एवं बाहरी ताकतों द्वारा उनकी आबादी को नियंत्रित करने का एक प्रयास है और यह उनके बच्चों में बांझपन का कारण बनेगा। वे ज़ोर देकर कहते हैं कि उनके पारंपरिक औषधीय उपचार और अनुष्ठानिक आशीर्वाद ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह आध्यात्मिक गुरु, जो वास्तव में नेकनीयत किंतु अडिग व्यक्ति है, वास्तविक रूप से मानते हैं कि ये टीके हानिकारक होते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने अनुयायियों को इसका विरोध करने की सलाह दी है। इसके लिए वह टीकाकरण की कुछ कथित 'विफलताओं' और प्राचीन भविष्यवाणियों का उदाहरण देता है। पारंपरिक जीवन-शैली का पालन करने वाले समुदाय के लिए उसके निर्देश या सलाह सर्वोपरि हैं। इसके कारण व्यापक जागरूकता अभियानों के बावजूद, गाँव में टीकाकरण शिविरों का लगभग पूर्ण बहिष्कार किया गया है। आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जिनमें से कुछ स्थानीय हैं और जिन्हें सामाजिक बहिष्कार या यहाँ तक कि शारीरिक हमले का भय है, तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अत्यधिक दबाव बना रहा है और चेतावनी दे रहा है कि यदि कोई ज़िला इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही, विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में न किया जाए क्योंकि इससे जन असंतोष उत्पन्न हो सकता है। साथ ही, विभाग ने 'सहमति-आधारित' लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया है। इसी बीच, एक बड़ा वार्षिक मेला आयोजित होने वाला है जिसमें कई गाँवों और क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे। यदि यह गाँव बिना टीकाकरण के रह गया, तो इससे खसरा-रूबेला (MR) के प्रकोप के प्रसार का तात्कालिक और गंभीर खतरा है, जो पूरे जिले और संभवतः उससे आगे तक फैल सकता है।

- उपर्युक्त प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
- इस विरोध को शांत करने के लिए आपके पास तत्काल क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- अंधविश्वास के व्यापक प्रभाव को दूर करने और संधारणीय लोक स्वास्थ्य परिणामों हेतु वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आप कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियां और प्रणालीगत सुधारों का सुझाव देंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are a dedicated District Health Officer (DHO) with a strong commitment to evidence-based public health practices, recently assigned to a remote district in India. Your immediate and most critical task is to lead a crucial district-wide Measles-Rubella (MR) vaccination drive, aimed at achieving 100% immunization coverage among children aged 9 months to 15 years. The success of this drive is vital for the collective health of thousands of children and for the district's overall health indicators, especially with the impending monsoon season posing additional health challenges.

However, in one of the largest and most traditional villages in your district, you encounter formidable resistance. The villagers, deeply influenced by the pronouncements of a revered local

spiritual leader, firmly believe that vaccinations are an intrusion by malevolent spirits, an attempt by external forces to control their population, or will cause infertility in their children. They insist that their traditional herbal remedies and ritualistic blessings are sufficient protection. This spiritual leader, a genuinely well-meaning but unyielding figure, sincerely believes these vaccinations are harmful and has publicly advised his followers against them, citing anecdotal 'failures' and ancient prophecies. His word is paramount for the community's adherence to traditional ways of life. This has led to an almost complete boycott of the vaccination camps in the village, despite extensive awareness campaigns. Your health workers, some of whom are local and fear social ostracization or even physical harm, are facing intense hostility. The state health department is exerting immense pressure to achieve targets, warning of severe consequences for any district failing to meet the immunization goals. Simultaneously, they strictly caution against any use of force that could lead to public unrest, emphasizing the need for 'consensus-based' public health. An impending large annual fair, which will draw crowds from multiple villages and regions, heightens the immediate and severe risk of a rapid MR outbreak if this village remains unvaccinated, posing a grave threat to the wider district and potentially beyond.

- Discuss the ethical issues involved in the above case.
- What are the immediate options available to you to overcome this resistance?
- What long-term strategies and systemic reforms would you suggest to address the pervasive influence of superstition and foster a scientific temperament for sustainable public health outcomes? (Answer in 250 words)

20

The case study points towards the prevalence of superstitions and blind-faith on one hand and medical health services on the other. According to SDG-3 "Good Health and Well Being", universalisation of healthcare is the only option for a healthy population.

(a) Ethical issues involved:

- ① Consensus-based vaccination in a vaccine-hesitant population
- ② Lack of education fuelling misinformation and fake news
- ③ Chances of a wide outbreak vs right to choice of people.
- ④ Blind faith vs scientific evidence.
- ⑤ Social ostracization vs violent behaviour.
- ⑥ Target completing vs people's hesitancy.

(b) Immediate options available:

- ① Opening a backchannel talk with spiritual leader.
  - ▷ Reminding him of the penal provisions for spreading misinformation
  - ▷ Asking him to clear the misunderstanding and convince people.
- ② Arranging a popular show and short video, highlighting the importance of MR vaccination.
- ③ Distributing free-tickets to people for free vaccination their child.
- ④ Distributing free school bags and bottles to children getting vaccinated  
↳ Children may urge their parents
- ⑤ Containment announcement for

the willage in case of non-vaccination

▷ long-term strategies and systemic reforms:

- ① Promoting genuine AYUSH practitioners:
- ② Disallowing superstition-spreading people to carry ground-gatherings.
- ③ Regular advertisements and incentives to discourage quacks and false narrative.
- ④ Opening medical facilities in backward areas and encouraging children to take medical profession.
- ⑤ Use of law against these squamous violence and vaccine hesitancy.

Superstition is a bane for a country of 1.4bn people where myths spread like fire. There is an urgent need to tackle this menace.

12.

आप एक अत्यंत प्रेरित और सिद्धांतवादी प्रधान ग्राम पंचायत सचिव हैं। हाल ही में, आपको एक दूरस्थ जिले में स्थित एक बड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण गाँव में पदस्थ किया गया है। आपका तात्कालिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 'ग्रामीण आवास योजना' के लाभार्थियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना है — यह राज्य की एक प्रमुख आवासीय योजना है, जिसका उद्देश्य वास्तव में गरीब और भूमिहीन परिवारों को 'पक्का' (ईंटों से बना) घर उपलब्ध कराना है। इस योजना की समय-सीमा बहुत कम है और निधियों की प्राप्ति सटीक व त्वरित लाभार्थी चयन पर निर्भर करती है। जिला कलेक्टर की ओर से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बल देते हुए किसी भी कदाचार के विरुद्ध स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गयी है।

वार्ड क्रमांक 3 में घर-घर जाकर मेहनत से किए गए आपके सत्यापन के दौरान, आपको पता चलता है कि श्री इंदर सिंह, एक व्यापक रूप से स्वीकृत 'बाहुबली' व्यक्ति है, जिसके परिवार के पास अपनी भूमि और व्यापक स्थानीय नेटवर्क की वजह से महत्वपूर्ण अनौपचारिक शक्ति और प्रभाव है, को अस्थायी रूप से एक पात्र लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अवस्थिति पर आपके द्वारा किए गए आकलन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री सिंह एक विशाल, बहुमंजिला 'पक्के' घर में रहता है और उसकी वित्तीय स्थिति 'गरीबी रेखा से नीचे' जीवन-यापन करने वाले परिवारों हेतु योजना के सख्त पात्रता मानदंडों से काफी ऊपर है। जब आप उसकी पात्रता पर प्रश्न उठाते हैं, तो श्री सिंह अत्यधिक आक्रामक हो जाता है। वह अपने परिवार के गाँव में 'अद्वितीय योगदान' और चल रहे उच्च प्राथमिकता वाले जिला स्तरीय 'जल सुरक्षा अभियान' के लिए समर्थन जुटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका नाम हटाने की किसी भी कोशिश को न केवल एक गंभीर व्यक्तिगत अपमान माना जाएगा, बल्कि इससे उनके परिवार द्वारा जल अभियान से महत्वपूर्ण समर्थन भी वापस लिया जा सकता है, जिससे पूरे जिले के प्रयास खतरे में पड़ सकते हैं और इससे हज़ारों किसान प्रभावित होंगे। उसने आगे चेतावनी दी कि वह भविष्य में होने वाले विकास कार्यों के विरुद्ध व्यापक स्थानीय प्रतिरोध को उग्र कर सकता है, जिससे पंचायत का कामकाज पूरी तरह ठप्प हो जाएगा।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि कई वास्तविक रूप से ऐसे गरीब परिवारों हैं जो जीर्ण-शीर्ण झोपड़ियों में रहते हैं और दशकों से ऐसी सहायता का इंतज़ार कर रहे हैं। श्री सिंह को शामिल करने से उनमें से किसी एक परिवार को अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर करना होगा। आपके खंड विकास अधिकारी (BDO), राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के भारी दबाव में, आपको व्यक्तिगत तौर पर 'विनम्र' होने और सभी सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 'समग्र शांति और सहयोग' को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। उन्होंने यह संकेत दिया है कि श्री सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को चुनौती देने से आपके पूरे कार्यकाल में 'अनावश्यक बाधाएं' उत्पन्न हो सकती हैं और आपकी भावी नियुक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ग्राम समुदाय, श्री सिंह के अनुचित दावे को जानकर भी, उनके विरुद्ध खुलकर बोलने से डरते हैं, जिससे उनकी अयोग्यता की बाह्य पुष्टि कठिन हो जाएगी और आप इस विषय पर अकेले पड़ जाएंगे।

- आपके समक्ष विद्यमान संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएं क्या हैं?
- आपके लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए।
- आप अपने निर्णय का नैतिक औचित्य सिद्ध करते हुए कौन-सी व्यापक कार्यवाही करेंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are a highly motivated and principle-driven Gram Panchayat Secretary, recently posted in a large and socio-economically diverse village in a remote district. Your immediate and most critical task is the meticulous verification of beneficiaries for the 'Gramin Awas Yojana' – a flagship state housing scheme aimed at providing 'pukka' (brick) houses to the genuinely impoverished and landless households. The scheme is under tight deadlines, with funds

dependent on swift and accurate beneficiary selection. The District Collector has explicitly warned against any malpractices, emphasizing fairness and transparency.

During your diligent house-to-house verification in Ward No. 3, you discover that Mr. Inder Singh, a widely acknowledged 'strongman' whose family wields significant informal power and influence due to their landholdings and extensive local network, has been provisionally listed as an eligible beneficiary. Your on-ground assessment unequivocally reveals that Mr. Singh resides in a sprawling, multi-story 'pucca' house and his financial status is demonstrably far above the scheme's strict eligibility criteria for 'Below Poverty Line' families. When you subtly question his eligibility, Mr. Singh becomes overtly aggressive, citing his family's 'unparalleled contribution' to the village and his crucial role in mobilizing support for the ongoing, high-priority district-level 'Jal Suraksha Abhiyan' (Water Conservation Campaign), where his active cooperation is currently indispensable. He bluntly states that any attempt to remove his name would not only be seen as a grave personal insult but could also result in his family's withdrawal of crucial support from the water campaign, potentially jeopardizing the entire district's efforts, which affects thousands of farmers. He further warns that he can incite widespread local resistance against future developmental works, effectively paralyzing the Panchayat's functioning.

You are keenly aware that several genuinely impoverished families, living in dilapidated shacks, have been waiting for decades for such assistance, and Mr. Singh's inclusion would directly mean one of them is unjustly excluded. Your Block Development Officer (BDO), under immense pressure to meet state targets, has privately advised you to be 'flexible' and prioritize 'overall peace and cooperation' to ensure the smooth rollout of all government schemes, hinting that challenging influential individuals like Mr. Singh might create 'unnecessary roadblocks' for your entire tenure and even impact your future postings. The village community, while silently aware of Mr. Singh's undue claim, fears openly speaking against him, making external validation of his ineligibility difficult and adding to your isolation.

- What are the potential administrative and ethical dilemmas you face?
- Discuss all options available to you.
- What comprehensive course of action would you choose to adopt, providing ethical justification for your decision? (Answer in 250 words)

20

The case study highlights the concentration of power with few individuals and misuse. Our constitution under Article - 39 unequivocally discards any such concentration and demands

equitable distribution of wealth and income.

▷ Stakeholders involved:

- ① Gram Panchayat secretary
- ② Mr. Indu Singh
- ③ District Collector
- ④ other beneficiaries under PMAY.
- ⑤ District people.
- ⑥ Government.

▷ Potential administrative and ethical dilemmas:

- ① Roadblock by Mr. Singh in fibre programs.
- ② Loss to thousands of people.
- ③ People are already aware about

found but everyone is silent.

- (4) Law and order situation
- (5) Personal loss in case of opposing Mr. Singh.
- (6) Corruption by letting Mr. Singh avail the benefit.
- (7) Pressure for secret list.

(B) ▷ Options available:

(1) Removing Mr. Singh's name:

Pros	Cons
▷ Genuine beneficiary	▷ Personal pressure due to political standing of Mr. Indu.
▷ Message to village people	▷ Roadblock to further programs
▷ Increase trust.	

② Discussing situation with collector:

Pros	Cons
▷ Viable situation under senior's guidance.	▷ May delay and complicate situation

③ Talking to Mr. Singh and explaining consequences of his actions.

Pros	Cons
▷ He may understand and agree.	▷ He may create further ruckus

④ Talking with local MHO's and village panchayat:

Pros	Cons
▷ Pressure on Mr. Singh from his community.	▷ They may not respond under his influence.

A mix of ①, ② & ④ has to be employed for successful action

(c) Comprehensive course of action:

- ① Revise the list and include genuine beneficiaries.
- ② Issue notice to Mr. Singh for detaching government employees.
- ③ Expedite the matter to higher authorities.
- ④ Inform local police in case of any action.
- ⑤ Take help of local leaders to explain the situation.

Cooperation is for the benefit of marginalised sections and no strong man may be allowed to hinder that.

**SPACE FOR ROUGH WORK**

VisionIAS

SPACE FOR ROUGH WORK

AL

VisionIAS